

वर्ष: 11	महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करने की तैयारी, डिजिटल प्रचार पर दिया गया जारे
अंक: 66	03
सोमवार, 03-09, जनवरी 2022	सर्वेक्षण तो यूपी में भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, परन्तु हकीकत क्या है?
मूल्य: 5 लं प्रति	08
ल 250 वार्षिक	भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, परन्तु हकीकत क्या है?

# 7 चरणों में होंगे यूपी के चुनाव

पंजाब, गोवा, उत्तराखण्ड में 1 फेज में मतदान, 10 मार्च को आएंगे नतीजे

एजेंसी

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखण्ड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही इन पांचों राज्यों में आचार संहिता भी लागू हो गया। पांचों राज्यों के चुनाव 7 फेज में होंगे। पहला चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। गोवा, पंजाब और उत्तराखण्ड में एक चरण में चुनाव। होंगे जबकि उत्तर प्रदेश में 7 पेज में चुनाव कराए जाएंगे। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में हो गोवा, उत्तराखण्ड और पंजाब में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में 7 पेज में चुनाव कराए जाएंगे। 24 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होगा। 14 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। 20 फरवरी को मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। 27 फरवरी और 3 मार्च को मणिपुर में चुनाव होंगे। आखिरी चरण के चुनाव 7 मार्च को कराए जाएंगे। 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे।



चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि 24.9 लाख मतदान इस बार पहली बार वोट डालेंगे। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इस बार महिला वोटरों की भागीदारी बढ़ेगी।

मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए। मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होंगे। पांचवें चरण के मतदान 27 फरवरी को होगा। छठे चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। 27 फरवरी और 3 मार्च को मणिपुर में चुनाव होंगे। आखिरी चरण के चुनाव 7 मार्च को कराए जाएंगे। 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे।

फ्लोर पर ही रहे। पोलिंग स्टेशन में 16 फीसदी की वृद्धि की गई है। कुल 215368 पोलिंग स्टेशन होंगे हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र देसा होगा जो विशेष रूप से महिला कमिंग्स द्वारा संचालित किया जाएगा। ताकि महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आंनलाइन नामांकन दाखिल करने का विकल्प भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 29% मतदान पहली वार वोट डालेंगे।

का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए।

भी कहा गया कि 24.9 लाख मतदान 5 जनवरी को प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा कि मतदान सूची इस बार पहली बार वोट डालेंगे। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि इस कारोड मतदान के मतदान 18.3 करोड मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि आगामी चुनाव में 18.3 वार महिला वोटरों की भागीदारी बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश में 29% मतदान पहली वार वोट डालेंगे।

का विकल्प भी दिया जाएगा।

का विकल्प भी दिय













## संपादकीय

## पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अनिनपरीक्षा की तरह हैं

पिछले दो लोकसभा चुनावों के बाद जिस प्रकार की राजनीतिक तस्वीर निर्मित हुई है, उससे यही परिलक्षित होता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बहुत बड़ी और कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रही है। अब देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की कवायद चल रही है। इन राज्यों में कांग्रेस की वर्तमान हालात परिस्थिति के ऐसे भंवर में गोता लगा रही है, जहां से वह अपनी राजनीतिक स्थिति में सुधार कर पाएगी, यह असंभव-सा ही लगत है। असंभव इसलिए भी कहा जा सकता है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहले से ही कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। और फिर वर्तमान के भाजपा शासन से उत्तर प्रदेश की भुक्तभोगी जनता बहुत ही संतुष्ट दिखाई दे रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वह जनता कह रही है जो पिछले शासन में दंबर्गी से परेशान थी। केवल दंबर्ग ही नहीं, बल्कि प्रशासन के आला अधिकारी भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके अपनी मनमानी करती थी, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की उस जनता को भुगतना पड़ता था जो बहुत ही संस्कारित भाव और ईमानदारी के साथ जीवन यापन करती थी। कौन नहीं जानता कि आज उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े दंबर्ग महारथी या तो रास्ते पर आ गए हैं या फिर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर शांत भाव से प्रदेश की योगी सरकार की कार्यशैली को बिना किसी ना नुकुर के देख रहे हैं। कांग्रेस की विसर्गति यह है कि आज के परिवृश्य में उसके साथ मिलकर कम से कम उत्तर प्रदेश में तो कोई भी दल चुनाव लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा सपना दिखाते हुए समाजवादी पार्टी को सत्ता सुख से वंचित कर दिया। अखिलेश यादव के सीने में यह टीस गाहे बगाहे उठती ही होगी। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि गांधी परिवार की विरासती पृष्ठभूमि से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाली श्रीमती प्रियंका वाड्रा भी वैसा राजनीतिक प्रभाव नहीं छोड़ पाई, जैसी उम्मीद की जा रही थी। इसमें कांग्रेस के कमजोर होने एक प्रामाणिक तथ्य यह भी है कि राहुल गांधी ने अपने परिवार की परंपरागत सीट अमेठी का परित्याग कर केरल की राजनीतिक पिच पर अपना खेल खेला। हालांकि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव अवश्य लड़ा, लेकिन भाजपा की ओर पूरी तैयारी करके जो चुनौती दी, राहुल

गांधी उस चुनाता का स्वाकार करन का स्थित म दिखाइ नहीं दिए और अमेठी से शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा । जहां तक उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब राज्य की बात करें तो वहां पिछले छह महीने पहले जो राजनीतिक दृश्य दिखाई देता था, आज का दृश्य उसके एकदम उलट है । पहले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस की एक छत्र कमान संभाले थे, आज वे कांग्रेस के लिए ही चुनौती बनकर राजनीतिक मैदान में हैं । यह भी लगभग तय ही हो गया है कि वे भाजपा के साथ दोस्ती करके चुनाव लड़ेंगे । इससे यह लगने लगा है कि भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भले ही लाभ न मिले, लेकिन कांग्रेस का रसातल की ओर जाना तय-सा लग रहा है । पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता बनाने लायक अपनी स्थिति मानकर चल रही थी, लेकिन अब उसके सपने पूरे होंगे या नहीं, संशय की स्थिति है । पंजाब में अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालकर किसान आंदोलन करने वाले 22 किसान संगठनों ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है । इस मोर्चा ने जोर दिखाया तो सबके सपने धूमिल भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं लगता । जब से कांग्रेस ने पराभव की ओर कहर्स बढ़ाया पारंशु किए हैं उस दिन के बात त तो कांग्रेस

का उत्तर करने वालों ने जागरूक हो, उत्तराधिकार का बाद जो राजनीति में अपनी स्थिति सुधारने की दिशा में कोई प्रयत्न हुए हैं और न ही ऐसा कोई प्रयास ही किया गया है। इसका मुख्य कारण यह भी माना जा रहा है कि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो प्रादेशिक क्षत्रियों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रख सके। इसको लेकर कांग्रेस में अंदर ही अंदर लावा सुलग रहा है, जिसकी हल्की-सी चिंगारी ने ही कांग्रेस को कमजोर किया है, लेकिन भविष्य में कांग्रेस के अंदर बड़े विस्फोट की भी आशंका निर्मित होने लगी है। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता असहज महसूस करने लगे हैं। वरिष्ठ नेता के रूप में पहचान बनाने वाले आज मायूस हैं। वे कभी खुलकर बगावत करने की स्थिति में दिखाई देते हैं तो कभी अपने प्रति होने वाली उपेक्षा से दुखी दिखाई देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक बार अपना दुख प्रकट करते हुए कहा था कि अब कांग्रेस में वरिष्ठों के दिन समाप्त हो चुके हैं। राहुल गांधी जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। इतना ही नहीं कई राजनेता पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग भी कई बार कर चुके हैं। यह मुद्दा लोकसभा चुनाव के बाद भी बहुत जोरदार से उठा था, लेकिन इस मांग को राष्ट्रीय नेतृत्व ने दरकिनार कर दिया। जिसका खामियाजा कांग्रेस को असंतोष के रूप में भोगना पड़ रहा है, अब आगे क्या होगा, यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह अवश्य ही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भविष्य की राह आसान नहीं है। वस्तुतः वर्तमान समय को कांग्रेस के लिए अग्रिमपरीक्षा निरूपित किया जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा और मणिपुर हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखकर यहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तैसा नमस्कार करने की स्थिति में

उत्तर प्रदेश ने कानून लाना चाहा लोकसभा नहीं है, जिसकी उसके नेता विरासती पृष्ठभूमि से राजनेता बनी प्रियंका वाड़ा से आशा कर रहे थे। उत्तराखण्ड में भी हालात इससे कम नहीं हैं। पंजाब में घमासान चल रहा है। वास्तव में इन सब बातों को सुधारने के लिए कांग्रेस को लोकतांत्रिक पद्धति से अपने प्रभावी नेताओं के दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद कांग्रेस के नेताओं को अपनी दशा सुधारने के लिए आत्ममंथन भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। पांच राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए किस प्रकार की स्थिति निर्मित करेंगे, यह अभी देखने का समय है।

# सर्वेक्षण तो यूपी में भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, परन्तु हकीकत क्या है?

## संजय सवसेन

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी लगातार नजदीक आती जा रही है। हफ्ते-दस दिन में चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लग जाएगी। 14 मार्च तक 18वीं विधान सभा का गठन हो जाना है। समय के साथ तमाम पार्टियों में प्रचार के साथ-साथ प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी तेजी पकड़ती जा रही है। टिकट के लिए दावेदारों में टक्कर तो दे रही है, लेकिन सत्ता में आने में कामयाब होती नहीं दिख रही है। तमाम सर्वेक्षणों का निचोड़ निकाला जाए तो इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी 230 से 249 सीटें जीत सकती है।

बनने के इतिहास को ठेंगा दिखाते हुए  
एक बार फिर योगी मुख्यमंत्री बनेंगे या  
अखिलेश यादव की पांच वर्ष के बाद  
सत्ता से वापसी होगी। बसपा सुप्रीमो  
मायावती या फिर कांग्रेस की  
महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका  
गांधी वाड़ा उनसे (योगी से) सत्ता  
छीनने में कामयाब रहेंगे? तमाम  
सर्वेक्षणों पर नजर ढौड़ाई जाए तो  
क्यास यही लगाए जा रहे हैं कि यूपी  
में एक बार फिर बीजेपी की सरकार  
बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी  
भाजपा को टक्कर तो दे रही है, लेकिन  
सत्ता में आने में कामयाब होती नहीं  
दिख रही है। तमाम सर्वेक्षणों का  
निचोड़ निकाला जाए तो इस वर्ष होने  
वाले विधानसभा चुनाव में 403 सीटें  
वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी 230  
से 249 सीटें जीत सकती है। वहीं,  
समाजवादी पार्टी 137 से 144 सीटें  
पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी और  
कांग्रेस के प्रदर्शन में इस बार भी सुधार



होता नहीं दिख रहा है। सर्वे के नतीजे कहते हैं कि मायावती की पार्टी जहां 9-14 सीटों पर सिमट सकती है तो कांग्रेस को महज 4-6 सीटों मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। यह जरूर है कि पूरे प्रदेश में एक की बायार नहीं बह रही है, कहीं बीजेपी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है तो कहीं समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है। तमाम चुनाव सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 38.6 फीसदी वोट मिल सकते हैं तो समाजवादी पार्टी 34.4 फीसदी वोट पाती दिख रही है। बसपा को 14.1 फीसदी तो कांग्रेस को 6.1 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 6.8 फीसदी वोट जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ज्यों ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है त्यों त्यों भाजपा के प्रति वोटरों की नाराजगी कम होती जा रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि योगी सरकार ने पिछले एक-डेढ़ वर्ष में जनता के लिए सरकारी खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। वोटर नहीं चाहते हैं कि किसी और को वोट देकर वह इस खजाने का रुख किसी और तरफ मोड़ दें। खैर पूरे प्रदेश के चुनाव की स्थितियों के अलग-अलग आकलन किया जाए ताकि सबसे दिलचस्प स्थिति पश्चिम यूपी की है। यहां समाजवादी पार्टी को फायदा है लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं नजर आ रही है। मतलब किसान आंदोलन और किसानों की नाराजगी के चलते बीजेपी को जितना नुकसान सोचा जा रहा था, उसे उतना नुकसान नहीं हो रहा है। सर्वे के मुताबिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव के मुकाबले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। लेकिन बीजेपी अब भी यह सबसे अधिक सीटें जीतती दिख रही है। पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में बीजेपी 57-60 जीत सकती है ताकि समाजवादी पार्टी 35-30 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बसपा कंगड़ा यहां 0-1 और कांग्रेस को 1-2 सीटें

मिलने को संभावना है। पश्चिम यूपी को लेकर सर्वे के नतीजे इसलिए भी दिलचस्प हैं, क्योंकि यूपी के इसी हिस्से में किसान आंदोलन का सबसे अधिक असर था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो गई है। बुंदेलखण्ड में भी बीजेपी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार बुंदेलखण्ड की करीब 18 सीटों में बीजेपी को 14-15 तो समाजवादी पार्टी को 3-5 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा को यहां पर एक सीट मिल सकती है तो कांग्रेस का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसी तरह से रुहेलखण्ड में बीजेपी 30-36 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है तो समाजवादी पार्टी के खाते में 17-18 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी को 1-2 तो कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अवध क्षेत्र में बीजेपी 57-65 सीटें जीत सकती है तो समाजवादी पार्टी यहां 31-33 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सर्वे के मुताबिक, बीएसपी को 3 सीटें मिल सकती है तो कांग्रेस 2-3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यहां 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। मध्य यूपी की बात करें तो यहां की 35 सीटों में से बीजेपी को 17-21 सीटें, तो समाजवादी पार्टी को 12-13 सीटें मिल सकती है। बीएसपी एवं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-1 सीटें रह सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल से ही समाजवादी पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। यहां कुल 102 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वांचल की वाराणसी सीट से ही प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव जीत कर जाते हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। यहां मोदी की प्रतिष्ठा सबसे अधिक दांव पर लगी है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी यहां 49-58 सीटें जीत सकती है तो समाजवादी पार्टी भी यहां 39 से 45 सीटें जीतती दिख रही है। बीएसपी को यहां 5-6 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस का यहां भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यूपी चुनाव में 'आप' (आम आदमी पार्टी) और ओवैसी की पार्टी वोट कटवा ही नजर आ रही हैं। यह दोनों दल किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे इसका पता नतीजे आने के बाद चलेगा। इसी प्रकार से भीम आर्मी बसपा के लिए नुकसानदायक सांकेत हो रही है। बात आम आदमी पार्टी की कि जाए तो उसके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जिसे वह यूपी में सीएम के रूप में आगे कर सके। कहने को संजय सिंह की यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनकी स्वयं की ही छवि विवादों से धिरी है, इसके चलते आप को वह कोई खास फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फिर भी फ्री की राजनीति करने में माहिर अरविंद केजरीवाल ने बोटों को कई तरह के लालच जरूर दे रखे हैं।

नेता ईलियां करें और जनता कोरोना प्रोटोकाल का पालन



यदि चुनावी रैलियों में सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसी प्रकार भारी भीड़ जुटाई जाती रही तो डर यही है कि कहीं फिर से वहाँ हालात न पैदा हों, जैसे मार्च-अप्रैल में चुनाव प्रचार के लिए रैलियों में जुटाई गई भारी भीड़ के चलते हुए थे।

योगेश कमार गोयल

देश में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों से दहशत का माहौल बन लगा है। लगभग तमाम विशेषज्ञ इसी की वजह से बढ़ रहे मामलों को देखा हुए फरवरी माह में तीसरी लहर की भविष्यवाणी करने लगे हैं। ऐसे में पहली से ही रोजी-रोटी के संकट से जूझ रहे करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य संबंध चिंताओं के साथ-साथ एक और लॉकडाउन लगने का डर अभी से सताया लगा है। दरअसल चंद दिनों में ही ओमिक्रॉन के देशभर में 700 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और यह आंकड़ा प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। इसके चलते कुछ राज्यों द्वारा 'नाइट कर्फ्यू' लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत कम ही है तेकिन जिस प्रकार कई देशों ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ाने वाला कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ताकतवर रूप में सामने आ रहा है, उससे तीसरी लहर की भविष्यवाणियां को लेकर चिंता का माहौल बनना स्वाभाविक ही है।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर इससे निपटने के लिए समय रहते केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी उपाय किए जाने की सख्त आवश्यकता है। 20 नवम्बर 2021 को जहां ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्शक्षण अफ्रीका से सामने आया था, वहीं भारत सहित पूरी दुनिया में केवल एक महीने के अंदर ही यह 110 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है और इस एक महीने में दुनियाभर में इस वेरिएंट के लाखों मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन फैलने की रफ्तार के आंकड़ों पर नजर डालें तो दर्शक्षण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के 95 फीसदी मामलों की प्रमुख वजह ओमिक्रॉन ही है। ब्रिटेन में जहां 29 नवम्बर तक ओमिक्रॉन के 0.17 फीसदी मामले सामने आ रहे थे, वहां 23 दिसम्बर तक इसके 38 फीसदी मामले दर्ज किए गए। यही हाल ही अमेरिका का भी है, जहां ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण दर में तेजी से बढ़ती रही है और 22 दिसम्बर तक दूर चौथा मामला ओमिक्रॉन का रहा।

वजह से ही सामने आ रहा है। भारत में भी यह संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी तेज हो गई है। दुनियाभर में फैलते ऑमिक्रॉन के कहर को लेकर चिंताजक स्थिति यह है कि इसमें अब तक कुल 53 म्यूटेशन हो चुके हैं औ यह डेल्टा के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा में कुल 18 और इस स्पाइक प्रोटीन में दो म्यूटेशन हुए थे लेकिन ऑमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन 32 म्यूटेशन हो चुके हैं जबकि इसके रिसेप्टर बाईंडिंग डोमेन में भी 1 म्यूटेशन हो चुके हैं। वायरस स्पाइक प्रोटीन के जरिये ही मानव शरीर प्रवेश करता है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट डॉ. टोमी पीकॉक के मुताबिक वायरस में जितने ज्यादा म्यूटेशन के जरिए वेरिएटी बनेगा, वह उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा और ऐसा वेरिएटी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑमिक्रोन को कई दिनों पहले ही 'वेरिएटी ऑफ कंसर्न' घोषित करते हुए कह चुका है कि तेजी से फैलता वाला यह वेरिएटी लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉ. मुसान हॉपकिंस का कहना है कि कोरोना का यह वेरिएटी दुनियाभर में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन सहित अन्य किसी भी वेरिएटी के मुकाबले बदतर होने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा वेरिएटी की आर वैल्यू 6-7 थी अर्थात् एक व्यक्ति वायरस को 6-7 व्यक्तियों में फैला सकता है जबकि ऑमिक्रॉन की आर वैल्यू 2-3 थी। ऑमिक्रॉन से संक्रमित परीक्षा 35-45 लोगों में संक्रमण फैलाया।

भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला 2 दिसंबर को सामने आया और उसके बाद से मूल वायरस के मुकाबले तीन गुना से भी ज्यादा तेरपत्तर से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का सबसे पहले प्रयोग वाली 'साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन' की अध्यक्ष डॉ एंजेलिक कोएत्जी का भारत के संदर्भ में कहना है कि कोरोना वायरस ने इस नए वेरिएंट के कारण यहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दिखें लेकिन मौजूदा टीकों से इस रोग को फैलने से रोकने में निश्चित ही मद मिलेगी किन्तु टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों को शत-प्रतिशत खत्म है। यही वजह है कि इस समय टीकाकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और बहुत सारी सेवाओं में टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है। एंजेलिक कोएत्जी का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति वायरिटीकाकरण हो चुका है या जो व्यक्ति पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है, उससे संक्रमण कम लोगों को फैलेगा और टीकाकरण न कराने वाले लोग वायरस को संभवतः शत-प्रतिशत फैलाएंगे। डॉ. एंजेलिक कोएत्जी के मुताबिक ओमिक्रॉन उच्च संक्रमण दर के साथ तेजी से फैल रहा है, लेकिन अस्पतालों में गंभीर मामले अपेक्षाकृत कम हैं। यह बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है और वे भी औसतन 5 से 6 दिन में टीक हो रहे हैं लेकिन ओमिक्रॉन भविष्य में अपना स्वरूप बदलकर अधिक घातक बन सकता है, इसलिए बेहद सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहने वाला अत्यधिकता है।

हिंदुत्व की राजनीति में भाजपा टाँपर भले है लेकिन और दलों के नेता भी अच्छे अंक लाते रहे हैं

नीरज कुमार दुल

अखिलेश हिंदुत्व की राजनीति में भाजपा का मुकाबला करने की तैयारी कर चुके हैं लेकिन सबाल यह है कि ऐसा करने से कहाँ उनका मुस्लिम वोटबैंक तो नहीं छिटक जायेगा ? विशेषज्ञों की माने तो ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि मुस्लिम वोटबैंक पूरी तरह उनके साथ खड़ा है । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं मथुरा राजनीति का केंद्रिंदु बनता जा रहा है । भाजपा नेता ही नहीं स्वयं मुख्यमंत्री भी मथुरा का मुद्दा उठा रहे हैं । ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि भगवान् श्रीकृष्ण उहें रोज सपने में आकर बताते हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है । अखिलेश यादव ने तो कुछ समय पहले यहाँ तक भी कहा था कि यदि अयोध्या मामले में फैसला आने के समय उनकी सरकार रही होती तो अब तक अयोध्या में राममंदिर बन भी गया होता । यही नहीं अखिलेश यादव ने गत रविवार को लखनऊ में गोसाईंगंज के पास स्थित महरुकलां गांव में नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी । इससे पहले जब पिछले साल हरिद्वार में कुंभ लगा था तब उसमें भी अखिलेश यादव गये थे । यही नहीं अखिलेश यादव जब-तब संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं । साफ है कि अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति में भाजपा का मुकाबला करने की तैयारी कर चुके हैं लेकिन सबाल यह है कि ऐसा करने से कहाँ उनका मुस्लिम वोटबैंक तो नहीं छिटक जायेगा ? विशेषज्ञों की माने तो ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि मुस्लिम वोटबैंक पूरी तरह उनके साथ खड़ा है । मुस्लिमों ने जैसे तमाम विकल्पों के बावजूद पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराने के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी का साथ दिया उसी तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी एकमुश्त तरीके से मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को ही पड़ने जा रहा है । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भले असदूरी ओवैसी कितनी रैलियां कर लें, भले अन्य पार्टियों के मुस्लिम नेता कितने बोट मांग लें, भले अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से किये गये कार्यों को कितना ही गिनाया जाये, लेकिन याद रखिये जब मतदान का वक्त आयेगा तब मुस्लिमों का बोट सपा और उसके गठबंधन सहयोगियों को ही पड़ेगा । अपनी बात को बजन देने के लिए आपको जरा पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव प्रचार की याद दिलाते हैं । उस समय ममता बनर्जी रैलियों में जिस तरह चंडी पाठ कर रही थीं उसको देखते हुए मीडिया के एक वर्ग में माना जा रहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग का बोट उनसे छिटक सकता है । लेकिन ऐसा नहीं हुआ । ममता को अपने वोटबैंक पर विश्वास था जिसके चलते मुस्लिमों का बोट तो उन्हें मिला ही साथ ही जिस तरह हिन्दुत्व की राजनीति में उन्होंने भाजपा का मुकाबला किया उससे हिंदुओं के बोट भी बड़ी संख्या में उन्हें मिले । अखिलेश यादव ठीक ममता बनर्जी की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं । उन्हें अपने मुस्लिम वोटबैंक पर विश्वास है और अब वह हिंदू खासकर सर्वांगी वोटरों को भी आकर्षित करने में जुटे हैं । तभी तो आत्मविश्वास में भरकर अखिलेश दावा कर रहे हैं कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण आकर उन्हें कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है । दूसरी ओर जहाँ तक मथुरा पर हो रही राजनीति की बात है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ धाम का भव्य निर्माण शुरू हो चुका है ऐसे में 'मथुरा वंदावन कैसे छूट जाएगा ।' देखना होता है ।

## संक्षिप्त समाचार

सीएसबी बैंक के एमडी-सीईओ राजेंद्रन ने कार्यकाल पूरा होने से पहले सेवानिवृत्ति ली

नई दिल्ली, एजेंसी। सीएसबी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ सी वी आर राजेंद्रन ने स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने का निर्णय लिया है। उनके उत्तराधिकारी की तलाश के लिए बैंक एक समिति का गठन करेगा। सीएसबी बैंक ने शेयर बाजार को जी जानकारी में बताया कि बैंक के निदेशक मंडल ने आठ जनवरी, 2022 को हुई बैंक में सी वी आर राजेंद्रन के समयावृत्त सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर विचार किया और इसे स्वीकार कर लिया। इसमें बताया गया कि निदेशक मंडल ने राजेंद्रन से अनुरोध किया है कि वह 31 मार्च, 2022 तक अपने पद पर बैठे रहें। उन्हें नौ दिसंबर, 2016 को बैंक का एमडी एवं सीईओ बनाया गया था और उनका कार्यकाल आठ दिसंबर, 2022 तक है। बैंक ने बताया कि निदेशक मंडल ने एमडी और सीईओ पद के लिए उम्मीदवार की एक समिति के गठन का फैसला किया है।

**बैंककर्मियों को भी दी जाए 'बूस्टर डोज', अग्रिम पंक्ति का कर्मचारी माना जाए:**  
एआईबीओसी



नई दिल्ली, एजेंसी। पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बैंक अधिकारियों के संगठन एआईबीओसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की है कि एहतिहासी खुशकाल (बूस्टर डोज) देने के लिए बैंक कर्मचारियों को भी अग्रिम पंक्ति का कर्मचारी (फ्रेटलाइन वर्कर) माना जाए। अग्रिम भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में सुझाव दिया कि वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए बैंकों को सप्ताह में पांच दिन खोला जाए। पत्र में यह आग्रह भी किया गया कि सभी शाखाओं या कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की प्रत्यक्ष उपस्थित होनी चाहिए, और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए। एआईबीओसी ने बैंक कर्मचारियों को उत्तराधीय रेलवे सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाने के लिए विशेष दर्जा देने की मांग भी की। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की एहतिहासी खुशकाली 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 60 साल तथा उससे अधिक उम्र के लोगों की जी जाएगी। एआईबीओसी के महासचिव सीमी दत्ता ने पत्र में कहा कि विभिन्न अंतराल पर बैंक कर्मचारियों की जीव करने के लिए अग्रिम रैपिड एंटीजन परिक्षण होना चाहिए। पत्र में कहा गया कि पहली दो लाख में लगभग 2,000 बैंक कर्मचारियों को अपील जाना गवाई। परिसंघ ने कहा, “हम युद्ध की विजेता सेना का हिस्सा मानते हैं, जिन्होंने बाधा दी है। लोकन इस प्रौजेक्ट को रेल मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी थी। आपको बता दें अभी भारतीय इलाके में इंफाल तक रेल लाइन है। रेलवे की इंडो-स्यामार रेल लिंक योजना के जरिये इंफाल से मोरेह तक ट्रैक बिछाया जाएगा।

**रिपोर्ट का दावा, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक जापान को पीछे छोड़ देगी**

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत वर्ष 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उस समय तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकार जर्मनी एवं ब्रिटेन से भी आगे हो जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह दशक काफी अचार रहने की सभावना जताई गई है। भारत इस समय अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी एवं ब्रिटेन के बाद दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के मुकाबिक भारत का बाजार मूल्य पर जीडीपी के वर्ष 2021 के 2,700 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 8,400 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस तीव्र उपतार वाली दुनिया से भारतीय जीडीपी का आकार 2030 तक जापान से आगे बढ़ाया जाए और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। आर्थिक एस मार्किंट की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था





